क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
4-0 ब्लोक, आगाम नवकार कॉम्पलेकक्ष, नीयर सचिन रेल्वे स्टेशन,सचिन, सूरत-394230
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
4-0 ब्लोक, आगाम नवकार कॉम्पलेकक्ष, नीयर सचिन रेल्वे स्टेशन,सचिन, सूरत-394230
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 166, मंगलवार, 10 जुलाई, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

वकीलों की दलील से लेकर जज के आदेश तक कोर्ट की पूरी कार्रवाई के लाइव प्रसारण की तैयारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म, इन-कैमरा सुनवाई और वैवाहिक विवादों को छोड़कर सभी मामलों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने के पक्ष में राय व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि कहा यह समय की जरूरत है । इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सोमवार को यह राय दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए व्यक्त की। कोर्ट ने अटॉर्नी जरनल के के वेणुगोपाल से कहा कि वह इस बारे में सुझाव दें, जिससे समग्र दिशानिर्देश बनाएं जा सकें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिर्फ संवैधानिक पीठ के समक्ष मामलों का ही सीधा प्रसारण नहीं होना चाहिए। बल्कि सभी मामलों का सीधा प्रसारण होना चाहिए। पीठ ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग से वादी को तुरंत यह पता चल जाएगा कि उसके मामले में क्या हो रहा है और उसका वकील कोर्ट में कैसा प्रदर्शन कर रहा है।

दो याचिकाएं दायर हुई थी

याचिकाकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह और स्वप्निल त्रिपाठी ने कहा कि मामलों को लाइव टेलीकास्ट लोगों की कोर्ट में पहुंच को बढ़ाएगा। साथ ही इससे केसों की गलत रिपोर्टिंग, त्रुटियों और बासी सूचनाओं के प्रसारण पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि वैवाहिक मामले और अन्य ऐसे मामले जिसमें निजता के मुद्दे हों, उनकी लाइव रिपोर्टिंग करने के बारे में कोर्ट को देखना पड़ेगा।

सूचना मौलिक अधिकार होने का तर्क

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि कोर्ट कार्यवाही की सूचनाएं लेना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि संविधान का मुख्य सिद्धांत यह है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। यह तब अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से प्रभावित होने वाला व्यक्ति उसका लाइव वीडियो देख सके।

कुछ मामले राष्ट्रीय महत्व के

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील पेश की गई कि कुछ फैसले ऐसे हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। जैसे आधार की वैधता, महिलाओं को मंदिरों में जाने का अधिकार तथा पारसी महिलाओं का विवाह के बाद अधिकार तथा समलैंगिक संबंधों को अपराध बनाने वाली धारा 377 को खत्म करने के मामले आदि।

फिलहाल विधायिका की कार्यवाही का प्रसारण

मौजूदा समय में संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही का सीधा प्रसाण होता है। सबसे पहले लोकसभा की चुनिंदा कार्यवाही का प्रसारण 1989 में हुआ।

कार्यवाही के लाइव् स्ट्रीमिंग के फायदे

-वादी को अपने केस की त्वरित स्थिति का सही पता लगेगा

-वकील की अदालत में परफार्मेंस का पता लगेगा

-वादी को गुमराह नहीं बनाया जा सकेगा

-केस को समझने तथा उसकी खामियां समय से दुरुस्त की जा सकेंगी।

-मामलों की गलत रिपोर्टिंग नहीं होगी तथा दूसरे माध्यमों से सूचना पर रोक लगेगी।

छात्रा के मिड डे मील छूने पर कुक ने फेंका खाना

उदयपुर (एजेंसी)। राजस्थान के उदयपुर जिले में एक सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन पकाने वाली संविदाकर्मी महिला को नाबालिग छात्रा के साथ कथित भेदभाव के आरोप में सोमवार को हटा दिया गया। सरकारी स्कूल में गत दो जुलाई को कमला वैष्णव ने पकाए गए मिड डे मील को मेघवाल समाज की आठवीं कक्षा की छात्रा द्वारा छूने पर छात्रा के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया और खाने को फेंक दिया। पीड़ित छात्रा द्वारा घटना की जानकारी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर रविवार को वायरल होने पर स्थानीय समाज के लोगों में असंतोष होने के बाद स्कूल प्रशासन कमेटी ने सोमवार को मिड डे मील बनाने वाली महिला को स्कूल से निकालने का निर्णय लिया। उदयपुर के उतरदा के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सुशील आर्य ने बताया कि खाना पकाने वाली महिला ने छात्रा से भेदभाव करने के लिए माफी मांग ली। स्थानीय लोग महिला पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

निर्भया के दोषियों को फांसी ही होगी

सजा बरकरार

● सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि रिव्यू के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। जो पॉइंट्स उठाए गए हैं उसमें कोई नया ग्राउंड नहीं दिखता है

दोषियों के पास बस ये 2 रास्ते

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले में 4 में से 3 दोषियों की रिव्यू पिटिशन खारिज कर दी है। इसके साथ ही अब दोषियों के पास दया के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं। दोषी करार दिए चारों मुजरिमों के पास क्यूरेटिव पिटिशन डालने का विकल्प है। अगर वहां भी याचिका खारिज हो जाती है तो राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति भी चारों की दया याचिका खारिज कर देते हैं तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं होगा।

क्या है क्यूरेटिव पिटिशन: जब किसी मुजरिम की दया याचिका रिव्यू पिटिशन में खारिज कर दी जाती है तब क्यूरेटिव पिटिशन डालकर मुजरिम अपने लिए रहम की गुहार लगा सकता है।

सीजेआई मिश्रा की बेंच ने सुनाया था फैसला: चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली बेंच ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी जिसके बाद इन दोषियों ने एक-एक कर रिव्यू पिटिशन दाखिल की।

नई दिल्ली। मामले में दोषियों की रिव्यू पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई को पवन, विनय और मुकेश की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। चौथे दोषी अक्षय ने पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इन दोषियों के पास क्यूरेटिव पिटिशन और फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका का विकल्प ही बचता है। सोमवार को निर्भया का परिवार भी कोर्ट में मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि रिव्यू के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। जो पॉइंट्स उठाए गए हैं उसमें कोई नया ग्राउंड नहीं दिखता है। आखिरकार कोर्ट ने पिटिशन को खारिज कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2017 को निर्भया केस में चारों दोषी मुकेश, अक्षय, विनय और पवन को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है। अदालत ने कहा था कि पीड़िता ने अंतिम समय में जो बयान दिया, वह बेहद अहम और पुख्ता साक्ष्य हैं। इस मामले ने देशभर के लोगों को झकझोर दिया था।

'सुप्रीम कोर्ट से इसी फैसले की उम्मीद थी'

नई दिल्ली। निर्भया के चार में से 3 दोषियों की फांसी की सजा के खिलाफ दायर रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले पर निर्भया के पैरंट्स ने खुशी जाहिर की। सुनवाई के दौरान निर्भया की मां और पिताजी कोर्ट रूम में मौजूद रहे। फैसला आने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि वह दोषियों को फांसी के फंदे पर देखना चाहते हैं। निर्भया के पिता बद्रीनाथ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। '6 साल से हम बस उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हमारी बेटी के दोषियों को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा।'

नोटबंदी के बाद नए नोटों की ढुलाई में वायुसेना ने निभाई थी अहम भूमिका

नई दिल्ली (एजेंसी) नोटबंदी के बाद जारी किए गए 2000 और 500 रुपए के नए नोटों की ढुलाई में भारतीय वायु सेना के अत्याधुनिक परिवहन विमान-सी-17 और सी-130 जे सुपर हरक्यूलिस के इस्तेमाल पर 29.41 करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च की गई।

अब सरकार को थमाया 29.41 करोड़ रुपए का बिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर 2016 को 500 और एकहजार रुपए के पुराने नोटों को प्रचलन से बाहर करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री की इस घोषणा से 86 फीसदी नोट व्यवस्था से बाहर हो गए थे। इसकी भरपाई नोटबंदी के बाद जारी 2000 और 500 रुपए के नए नोटों से अविलंब करने की आवश्यकता थी। भारतीय वायु सेना द्वारा एक आरटीआई आवेदन का दिए गए जवाब के अनुसार सरकार के आठ नवंबर 2016 को 1000 और 500 रुपये के पुराने नोटों को अचानक से प्रचलन से बाहर करने के बाद उसके परिवहन विमानों सी -17 और सी -130 जे सुपर हरक्यूलिस ने सेक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस और टकसालों से देश के विभिन्न हिस्सों में नोटों की ढुलाई करने के लिए 91 चक्कर लगाए। आरबीआई और सरकारी आंकड़ों के अनुसार आठ नवंबर तक 500 के 1716.5 करोड़ नोट थे और 1000 रुपए के 685.8 करोड़ नोट थे। इस तरह इन नोटों का कुल मूल्य 15.44 लाख करोड़ रुपए था जो उस समय प्रचलन में मौजूद कुल मुद्रा का तकरीबन 86 फीसदी था। सेवानिवृत्त कोमोडोर लोकेश बत्रा की आरटीआई के जवाब में वायु सेना ने कहा कि उसने सरकारी स्वामित्व वाले सेक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड को अपनी सेवाओं के बदले में 29.41 करोड़ रुपए का बिल सौंपा है। बत्रा ने कहा कि मेरी राय है कि सरकार को रक्षा परिसंपत्ति के इस्तेमाल से बचना चाहिए था और इसकी जगह असैन्य परिवहन विमान की सेवाएं आसानी से ली जा सकती थीं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने नोटबंदी की घोषणा करने से पहले खुद को पूरी तरह तैयार किया होता तो इस तरह की स्थिति से बचा जा सकता था। नोटबंदी के बाद सरकार ने 2016-17 में 500-2000 और अन्य मूल्य के नये नोटों की छपाई पर 7965 करोड़ खर्च किये थे। इस मद में पिछले वर्ष में खर्च की गई 3421 करोड़ की रकम की तुलना में यह दोगुनी राशि थी।

सुषमा ने हमले में घायल इकबाल सिंह का हाल जाना

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अफगानिस्तान में एक आत्मघाती हमले में घायल हुए सरदार इकबाल सिंह से बातचीत कर उनका हालचाल पूछा है। सरदार इकबाल सिंह को अफगानिस्तान से लाकर यहां एम्स में भर्ती कराया गया है।

श्रीमती स्वराज ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि उन्होंने सरदार इकबाल सिंह से बातचीत की है। उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है और उन्हें अगले सप्ताह अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी हर संभव मदद कर रही है। गत एक जुलाई को हुए इस आत्मघाती हमले में 19 लोगों की मौत हो गयी थी और कई अन्य घायल हो गये थे।

कांग्रेस पर उलटा पड़ गया मोदी को घेरने का दांव

आईटी सेल की प्रमुख दिव्या स्पंदना ने गलती के लिए सोशल मीडिया पर मांगी माफी

नई दिल्ली (एजेंसी)। वर्ष 2019 में होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर सभी दल सोशल मीडिया का जमकर सहारा ले रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच कई बार जुबानी जंग देखने को मिली है। लेकिन अबकी बार मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कांग्रेस पर उलटा पड़ गया। कांग्रेस के आईटी सेल की प्रमुख दिव्या स्पंदना को अपनी इस गलती के लिए सोशल मीडिया पर माफी तक मांगनी पड़ी।

दरअसल दिव्या ने शनिवार को ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को लेकर दावा किया कि यह पीएम मोदी की जयपुर में हुई रैली का है। इस वीडियो में गुस्साई भीड़ राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं, %मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। वीडियो साझा करते हुए दिव्या ने लिखा कि कुछ अजीब कारणों की वजह से फेसबुक पर अपलोड नहीं हो पा रहा है। कुछ ही देर में यह वीडियो वायरल हो गया। जिसके बाद यह बात सामने आई कि यह वीडियो पांच महीने पुराना है। दिव्या को जैसे ही अपनी गलत का अहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत इसके लिए माफी मांगी। हालांकि उनके इस पोस्ट को लेकर राजनीति भी गरमा गई।

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस ने हमेशा की तरह ट्विटर पर सेल्फ गोल किया है। वहीं दिव्या ने मालवीय के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि हां हमसे वह गलती हुई है लेकिन वह कंटेट असली है। क्या आप इसपर संज्ञान लेंगे अमित? एक मजबूत नेता होकर इसे स्वीकार करें। कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसते हुए ट्विट किया कि उप्स.. यह वीडियो जयपुर का नहीं बल्कि झुंझनू का है। जहां पीएम मोदी और सीएम वसुंधरा राजे मौजूद थीं।

स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर भाग रहे अपराधी की पीट-पीट कर हत्या

सीवान (एजेंसी)। बिहार में सीवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रविवार को दिनदहाड़े लूटपाट के दौरान एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर भाग रहे एक अपराधी को उग्र भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला जबकि एक अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि अपराह्न करीब तीन बजे छह की संख्या में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंद अपराधी श्याम बाजार स्थित अजय वर्मा के सोने-चांदी की दुकान में प्रवेश कर गये। इसके बाद अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर लूटपाट की कोशिश की और विरोध करने पर व्यवसायी अजय को गोली मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोग इकट्ठा हो गये और भाग रहे अपराधियों में से तीन को पकड़ लिया और एक की पीट-पीट कर हत्या कर दी तथा एक अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूत्रों ने बताया कि घायल अपराधी और व्यवसायी को सीवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान गोपालगंज जिला निवासी सचिन (25) के रूप में की गयी है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस एक अन्य गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के आधार पर तीन अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

मोदी सरकार आने के बाद गलत दिशा की और बढ़ा देश : अमर्त्य सेन

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद से सामाजिक क्षेत्रों में ध्यान नहीं दिया है, जिस कारण देश गलत दिशा में जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहली सरकारों के मुकाबले मोदी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई खास कदम नहीं उठाया है।

अमर्त्य सेन ने शनिवार को अपनी नई पुस्तक 'भारत और उसके विरोधाभास' पर चर्चा के दौरान कहा कि मोदी सरकार के आने से चीजें बहुत खराब हो गई हैं। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य में पर्याप्त काम नहीं किया है और 2014 के बाद से इन क्षेत्रों में गलत दिशा की ओर बढ़े हैं। इस किताब के सहलेखक अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज हैं। अमर्त्य सेन ने अपने संबोधन में कहा कि 20 साल पहले इस क्षेत्र के छह देशों में भारत, श्रीलंका के बाद दूसरा बेहतरीन देश था, लेकिन अब यह दूसरा सबसे खराब देश है।

अर्थशास्त्री ने कहा कि पाकिस्तान की समस्याओं की वजह से इस्लामाबाद ने हमें बचा लिया है, लेकिन भारत के लोगों को उन चीजों को लेकर गौरवान्वित होने की जरूरत है, जो हमारे पास हैं लेकिन साथ मैं कई चीजों पर शर्मिंदा होने की भी जरूरत है। अपनी नई किताब पर चर्चा के दौरान अमर्त्य सेन ने प्रख्यात लेखक वीएस नायपॉल का जिक्र करते हुए कहा कि एक महान लेखक ने 'ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास' जैसा उपन्यास लिखा था। उन्हें यह भी लिखना चाहिए था कि 13वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, जब हिंदू मंदिरों और हिंदू सभ्यता का विनाश हुआ। उन्होंने कहा कि हम पतन की ओर जा रहे हैं और अगर ऐसा है तो हमें इसे रोकने के लिए प्रयास करने होंगे। सेन ने कहा कि यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो हम बांग्लादेश की माली हालत के बावजूद उससे पीछे हैं।

भूटान से 10 किलो सोना ला रहे दो तस्कर गिरफ्तार

सिलीगुड़ी (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआईआर) ने भूटान से सोना तस्करी कर दिल्ली ला रहे दो लोगों को यहां गिरफ्तार कर उनके पास से 10 किलो सोना बरामद किया। डीआईआर के एक अधिकारी ने बताया कि यह सोना बिस्कुट के रूप में था और इसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपये से अधिक है।

उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान दिल्ली निवासी सौरभ कुमार जैन और बिहार निवासी दिलीप चौरसिया के रूप में हुई है। सोने को चारपहिया वाहन में विशेष रूप तैयार की गयी सीट के नीचे छिपाकर रखा गया था। डीआरआई अधिकारियों ने शनिवार रात फुलबाड़ी बाइपास के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों और उनके पास से जब्त किये गये सोने को रविवार को स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।

भूमि-पूजन

60 करोड़ रुपए की लागत से रीवा में बनेगा पत्रकारिता विवि परिसर

पत्रकारिता से जुड़े सभी कोर्स होंगे संचालित : शुक्ल

भोपाल (एजेंसी) उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा के लिए आज ऐतिहासिक क्षण है। विंध्य और रीवा में पत्रकारिता की समृद्ध विरासत रही है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के परिसर निर्माण के साथ इस विरासत के पुनर्जीवन का क्षण आया है। उन्होंने कहा कि इस परिसर में पत्रकारिता के सभी आयामों से जुड़े कोर्स संचालित होंगे।

इससे पत्रकारिता को नई दिशा देने वाले पत्रकार तथा मीडिया पर्सन तैयार होंगे। उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल एवं हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कृष्णमुरारी मोघे ने विधिवत भूमिपूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इसका निर्माण 60 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। शुक्ल ने कहा कि राजनीति तथा पत्रकारिता विंध्य और रीवा के खून में है। हमें राजनीति और पत्रकारिता की शिक्षा बचपन से ही दी जाती है। इसलिए पत्रकारिता विश्वविद्यालय का प्रयोग रीवा में सबसे सफल सिद्ध होगा। इस भव्य परिसर में सभी आधुनिक सूचना तकनीक की जानकारी दी जायेगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय एशिया का अनोखा विश्वविद्यालय है। उसके भव्य परिसर निर्माण से यहां के युवाओं को पत्रकारिता के प्रशिक्षण के लिये हर तरह की सुविधा उपलब्ध होगी। रीवा को हम एजुकेशन का हब बनायेंगे। उद्योग मंत्री ने रीवा में हो रहे सतत विकास तथा निर्माण कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कृष्णा राजकपूर आडिटोरियम निर्माण से कला को नया आयाम मिलेगा उसी तरह पत्रकारिता परिसर निर्माण से पत्रकारिता को नया आयाम मिलेगा।

समय सीमा में होगा पत्रकारिता परिसर का निर्माण : मोघे

हाउसिंग बोड के अध्यक्ष मोघे ने कहा कि पत्रकारिता परिसर का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तथा भव्य निर्माण कराया जाएगा। यह भवन विंध्य की पत्रकारिता के स्वर्णिम इतिहास को निरूपित करेगा। महापौर श्रीमती ममता गुप्ता ने कहा कि इस परिसर निर्माण से क्षेत्र की पत्रकारिता को नई गति मिलेगी। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति जगदीश उपासने ने कहा कि समय के साथ समाचार भेजने के साधन बदल रहे हैं। पत्रकारिता को सदैव समाज और देश की चिन्ता करनी चाहिए। कुलाधिसचिव तथा पूर्व संचालक जनसम्पर्क लाजपत आहूजा ने कहा कि विन्ध्य ऐसा क्षेत्र है जिसके एक सेनापति लाल बलदेव सिंह तथा विन्ध्य के मुख्यमंत्री रहते हुए पंडित शंभूनाथ शुक्ल अखबार का संपादन करते रहे। ऐसा उदाहरण पूरे देश में नहीं है। पत्रकारिता की इसी ज्वाला को प्रज्वलित करने का कार्य पत्रकारिता विश्वविद्यालय परिसर करेगा।

हथियार के साथ कट्टर नक्सली गिरफ्तार

गिरिडीह (एजेंसी)। झारखंड के गिरिडीह जिले में चतरो और सतकटिया जंगल में सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की ओर से चलाए गए संयुक्त अभियान में अजय महतो दस्ता के कट्टर नक्सली सोनाराम हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर भारी संख्या में हथियार बरामद करने के साथ ही उनके चार बंकरों को ध्वस्त किया गया है।

एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने रविवार को यहां बताया कि सूचना मिली थी कि चतरो और सतकटिया जंगल में प्रतिबंधित नक्सली संगठन के अजय महतो और रामदयाल महतो का दस्ता सक्रिय है। उन्होंने बताया कि इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए जिला पुलिस, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर ने इन जंगलों में संयुक्त अभियान चलाया। श्री झा ने बताया कि सर्च अभियान के दौरान चतरो के जंगल क्षेत्र से एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसकी पहचान कट्टर नक्सली सोनाराम हेम्ब्रम उर्फ ब्रमदेव के रूप में की गई है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार नक्सली ने माना कि वह अजय महतो और रामदयाल महतो दस्ते का सक्रिय सदस्य है।

संपादकीय

खिलाड़ी का देश

खेल किसी देश या किसी भूगोल विशेष में भले ही शुरू होते हों, लेकिन माना यही जाता है कि खेल का कोई देश नहीं होता। वरना क्या बात थी कि भारत में क्रिकेट इतना लोकप्रिय हो जाता, या कई दशकों तक हॉकी का ताज भारत के सिर पर ही सजता। इसी तरह फुटबॉल है, जो सदियों पहले किसी रूप में शुरू, तो चीन में हुआ था, पर आज पूरी दुनिया में खेला जाता है और दिलचस्प यह है कि दुनिया के श्रेष्ठ फुटबॉल टीमों में चीन का नाम कहीं नहीं आता। खेल भले ही किसी देश का न होता हो, लेकिन खिलाड़ियों के बारे में आम धारणा यही है कि वे एक देश विशेष के होते हैं और उसके गौरव के लिए जी-जान लड़ा देते हैं। कुछ हद तक यह सही भी है, लेकिन हकीकत पूरी तरह ऐसी नहीं है। कम से कम फुटबॉल में तो नहीं ही है। इस समय जब रूस में विश्व कप फुटबॉल चल रहा है, तो वहां खेल रहे हर दस खिलाड़ियों में एक ऐसा है, जो उस देश से नहीं खेल रहा, जहां वह पैदा हुआ है। मोरक्को की टीम में तो 61.5 फीसदी खिलाड़ी ऐसे हैं, जो वहां पैदा नहीं हुए। इसी तरह सेनेगल की टीम के 39.4 प्रतिशत और पुर्तगाल की टीम के 32.1 प्रतिशत खिलाड़ी विदेश में जन्मे हैं। वे भले ही पैदा कहीं भी हुए हों, पर उनकी पहचान उस देश के खिलाड़ी के रूप में ही है, जिस देश की टीम में वे खेलते हैं। हालांकि ब्राजील, जर्मनी और मेक्सिको की टीम में कोई विदेशी खिलाड़ी नहीं है। ये तो हुई विश्व कप खेलने के लिए रूस पहुंचे कुल 1032 खिलाड़ियों की बात। अब अगर हम इसके आगे जाकर कई देशों में होने वाली राष्ट्रीय फुटबॉल लीग को देखें, तो वहां नजारा और भी दिलचस्प होता है। सबसे पहले हम फुटबॉल के मौजूदा सबसे लोकप्रिय माने जाने वाले खिलाड़ियों में एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही लेते हैं। वह पुर्तगाल में पैदा हुए हैं और विश्व कप में पुर्तगाल की टीम में ही खेल रहे हैं। लेकिन जब फुटबॉल लीग की बात होती है, तो वह लगातार इंग्लिश और स्पेनिश लीग में स्थानीय टीमों के साथ खेलते हैं। रोनाल्डो ही नहीं, यह स्थिति बहुत से दूसरे खिलाड़ियों की भी है। यह ठीक वैसे ही है, जैसे हमारी टी-20 क्रिकेट लीग आईपीएल में दुनिया भर के खिलाड़ी दिल्ली, चेन्नई, राजस्थान, बेंगलुरु आदि की टीमों के साथ खेलते हैं। फुटबॉल में सबसे दिलचस्प मामला है क्रोएशिया का। इसके शत-प्रतिशत खिलाड़ी विदेशी लीग में खेलते हैं। क्रोएशिया छोटा सा देश है और इसके लिए अपनी लीग करना संभव नहीं है। फिर क्रोएशिया के लिए भी यह जरूरी है कि उसके खिलाड़ी अपना स्तर बनाए रखने के लिए लगातार विश्वस्तरीय टीमों से खेलते रहें। जाहिर है, इससे खिलाड़ियों को खासा पैसा भी मिल जाता है। अच्छे खिलाड़ी मिलें, इसके लिए लीग खेलने वाले क्लबों के चयनकर्ता दुनिया भर, खासकर अफ्रीकी देशों में, नई प्रतिभाओं को खोजने के लिए खाक छानते घूमते हैं। यह काम फुटबॉल को दिलचस्प ही नहीं बनाए रखता, उसे विविधता भी देता है। खेल अभी भी दुनिया के ऐसे कौशल हैं, जहां प्रतिभाएं कारखानों या प्रयोगशालाओं में नहीं बनाई जातीं, बल्कि जमीन पर खोजी जाती हैं। फुटबॉल में इसके लिए जो कवायद चलती है, वह न सिर्फ इस खेल को लगातार नया निखार देती रहती है, बल्कि उसकी लोकप्रियता भी लगातार नई ऊंचाई पर पहुंचती है। काश, बाकी दुनिया में भी वही होता, जो फुटबॉल में होता है।.

नवाज को सजा

पाकिस्तान में नवाज शरीफ एवं उनके परिवार को मिली सजा के बाद यह प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है कि आखिर वहां की राजनीति अब किस दिशा में जाएगी और भारत से उसके संबंध कैसे रहेंगे? बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद शरीफ राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र जनाधार वाले नेता बच गए थे। इमरान खान एक नेता के तौर पर उभरे जरूर हैं, किंतु उनकी पार्टी का वैसा संगठन नहीं जैसा नवाज के पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन का है। शरीफ ने धीरे-धीरे अपनी बेटी मरियम को राजनीति में सक्रिय किया था। मरियम भी चुनाव में खड़ीं थीं। मरियम पति-पत्नी को भी सजा मिल गई है। मरियम की उम्मीदवारी को चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। नवाज के भाई शहबाज शरीफ पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, पर उनकी देशव्यापी वैसी छवि नहीं है। शहबाज पार्टी के नेता के रूप में स्वीकार्य होंगे और देश भी उनको स्वीकार कर लेगा ऐसी स्थिति इस समय नहीं है। ऐन चुनाव के बीच यह फैसला पाकिस्तान की राजनीति में खालीपन लेकर आया है। हालांकि पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने नवाज को पहले ही चुनाव लड़ने और पार्टी में कोई पद लेने के अयोग्य ठहरा दिया था, इसलिए वो प्रत्यक्ष तो नेतृत्व नहीं कर सकते थे पर उनकी उपस्थिति बड़ा असर डालती। वे अपनी पत्नी के इलाज के लिए लंदन जाने के पहले प्रचार तो कर ही रहे थे। दूसरी ओर, बेनजीर भुट्टो के बाद पीपीपी भले हत्या की सहानुभूति में सत्ता में आ गई मगर आसिफ अली जरदारी या बिलाल भुट्टो का वह कद नहीं बन पाया है। परवेज मुशर्रफ के राजनीतिक भविष्य को वहां के न्यायालयों में विराजमान कट्टरपंथियों ने खत्म कर दिया है। इस तरह राष्ट्रीय स्तर पर ले-देकर इमरान खान बचते हैं। सेना उनकी पीठ पर है और न्यायपालिका के कट्टरपंथियों का भी उनको समर्थन है। अगर तहरीक-ए-इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है तो सेना उनकी सरकार गठित करने में भूमिका निभा सकती है। जाहिर है, वैसी स्थिति में उनके शासन में सेना की भूमिका ज्यादा प्रबल होगी। नवाज ने कोशिश की थी सेना, आईएसआई और कट्टरपंथियों से मुक्त होकर शासन चलाने, भारत से संबंध सुधारने और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तो उनकी ऐसी दशा कर दी गई। उसके बाद कौन होगा जो निकट भविष्य में अपनी राजनीति को ऐसी जोखिम में डालेगा?

कटाक्ष/ कबीरदास

बनना होगा दधीचि

पश्चिमी देशों के मुकाबले भारतीय समाज अंगदान को लेकर बहुत उत्साहित नहीं रहा है। इसके पीछे उसके धार्मिक पूर्वाग्रह सामने आ जाते हैं। जैसे पुनर्जन्म के बाद अपंगता का शिकार होना वगैरह। इस प्रकार के धार्मिक पूर्वाग्रहों ने अंगदान को बुरी तरह से हतोत्साहित किया है। जिस कारण बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों को अंग नहीं मिल पाते। पूर्वाग्रहों के बीच नेत्रदान क्षेत्र से एक अच्छी खबर है, जहां ''नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस' ने 2017-18 के लिए 50 हजार नेत्रदान लक्ष्य को पूरा कर लिया। 50 हजार के लक्ष्य को पार करते हुए यह आंकड़ा 69 हजार 343 तक पहुंच चुका है। एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी देते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वैच्छिक नेत्रदान को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ में ''उत्तम आचार' को स्कूली बच्चों में समाहित करने पर बल दिया। आंखों की व्यापक देखभाल सेवाएं प्रदान करने, और उसके लिए सुविधाओं पर भी अपनी राय दी। उप राष्ट्रपति के विचार स्वागतयोग्य हैं। बच्चों की मानसिकता को अंगदान के लिए प्रेरित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ों के पूर्वाग्रहों को तोड़ना कठिन होता है। वो अपनी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ जाती हैं। दूसरा अहम बिंदु है जागरूकता का, जिसे सतत चलाए रखने की दरकार है। अंगदान से लाभान्वित होने वालों की कहानियों को प्रभावी तरीके से प्रसारित करने से अंगदान को लेकर जनता में बेहतर समझ पैदा होगी। लिहाजा इसमें अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। अंगदान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। समय पर अंग का प्रत्यारोपण-उदाहरण के तौर पर नेत्रदान को ही लें-जिसे व्यक्ति के मृत्यु के 6 से 8 घंटे के अंदर निकाल कर 24 घंटे के भीतर ही प्रत्यारोपित कराना होता है। आंखों के मामलों में तो भारत बेहतर हालात में है, मगर अन्य अंग मसलन लीवर, किडनी, हार्ट और त्वचा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अंगों को संरक्षित रखने वाले बैंकों की बेहद कमी है, जिसकी वजह से अंग बेकार हो जाते हैं। भारत तो महर्षि दधीचि की भूमि है, जिन्होंने आसुरी शक्तियों को पराजित करने को हथियार निर्माण के लिए अपना शरीर देवताओं को दान कर दिया था, अगर सरकार जागरूकता के साथ अंगदान बैंकों को विस्तार करे तो स्वास्थ्य अनुसंधान में क्रांति हो सकती है।

नवाज के सामने कुआं और खाई

सुशांत सरीन

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए 'सजा' तो पिछले साल जनवरी में ही तय हो गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ खारिज किए गए 'रेफरेन्स' यानी मामले को फिर से खोलने का निर्देश दिया। ये 'रेफरेन्स'पनामा पेपर लीक से जुड़े हुए थे। विडंबना है कि जिस पनामा कांड में नवाज शरीफ का नाम ही नहीं है, उसमें उन्हें यह सजा दी गई है। इस मामले में तो उनके बच्चों के नाम सीधे तौर आए हैं। दिलचस्प यह भी है कि भ्रष्टाचार-निरोधक अदालत में जिस जज मुहम्मद बशीर ने मियां शरीफ को यह सजा सुनाई है, उन्हीं की अदालत में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भी ऐसे ही भ्रष्टाचार के 'रेफरेन्स' दाखिल किए गए थे। मगर जरदारी को उन तमाम मामलों से यह कहकर बरी कर दिया गया कि उनके खिलाफ कोई दस्तावेजी सुबूत नहीं है। नवाज शरीफ के वकीलों ने यह तर्क भी अदालत में दिए, मगर उन्हें मायूसी हाथ लगी। और नवाज शरीफ 10 वर्षों के लिए सलाखों के पीछे धकेल दिए गए हैं। एक ही जज, एक ही अदालत, एक जैसे मामले, फिर भी फैसला अलग-अलग। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह साफ-साफ यह है कि नवाज शरीफ अब सेना की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। पाकिस्तान भले ही अपनी न्यापालिका के निष्पक्ष होने का दावा करे, मगर असलियत में वहां की कानूनी प्रणालियों में कई छेद हैं। वहां 'डीप स्टेट' के करीबी होने का पूरा फायदा मिलता है। 'डीप स्टेट' फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के शीर्ष अधिकारियों का एक अनधिकृत ढांचा है, जो सियासत में पर्याप्त दखल रखता है। अगर यह साथ खड़ा हो, तो तमाम सुबूत खिलाफ होने पर भी अपराधी को सजा नहीं मिलती। लेकिन यदि 'डीप स्टेट' की नजर टेढ़ी हो जाए, तो सुबूतों का हक में होना भी आपको सजा से नहीं बचा सकता। यही पाकिस्तान की 'निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका' का पैमाना है। नवाज शरीफ इसी के शिकार बने हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम मामले उस वक्त अदालत में खारिज हो रहे थे, जब वह 'डीप स्टेट' के करीब थे, मगर इस रक्षा कवच के टूटते ही पहले वह दोषी साबित हुए और अब सजायाफ्ता। उनकी नई रणनीति ने भी मुश्किलें बढ़ाई हैं। जब से नवाज शरीफ को बर्खास्त किया गया था, वह देश भर में घूम-घूमकर चुनावी जलसों (सभाओं) को संबोधित कर रहे थे। वह लोगों को यह समझाने में सफल हो रहे थे कि उनके साथ गलत हुआ है। उन्हें साजिशन सत्ता से हटाया गया है। लिहाजा वोट की इज्जत के लिए उन्हें ही वोट मिलना चाहिए। मगर यह माहौल चरम पर पहुंच पाता कि बीमार पत्नी कुलसुम नवाज को देखने उन्हें अचानक लंदन जाना पड़ा। कुलसुम की हालत इस समय काफी नाजुक है। इधर, नवाज के भाई शहबाज शरीफ चुनाव प्रचार की उस लय को नहीं पकड़ पाए। एक सच यह भी है कि वह ऐसा करना ही नहीं चाहते। लगता है, वह फौज व अदालतों के सामने घुटने टेककर अपने लिए 'रहम' की फिराक में हैं। वह सुलह के लिए 'डीप स्टेट' के करीब जाने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज को भी तोड़ा गया। पार्टी के कई उम्मीदवारों ने ठीक उसी वक्त अपनी उम्मीदवारी छोड़ दी, जब चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। इन सबने नवाज शरीफ के पक्ष में बने माहौल को कमजोर कर दिया है। हालांकि पिछले महीने आए एक सर्वे का नतीजा बताता है कि अब भी वह एक बड़ी ताकत बने हुए हैं। पंजाब प्रांत में उन्हें बहुमत मिलने की बात कही गई है, जबकि कई अन्य सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई गई है। मगर यह सर्वे पिछले महीने का है, जबकि चुनावी माहौल में एक हफ्ते में ही 'हवा' बदल जाया करती है।

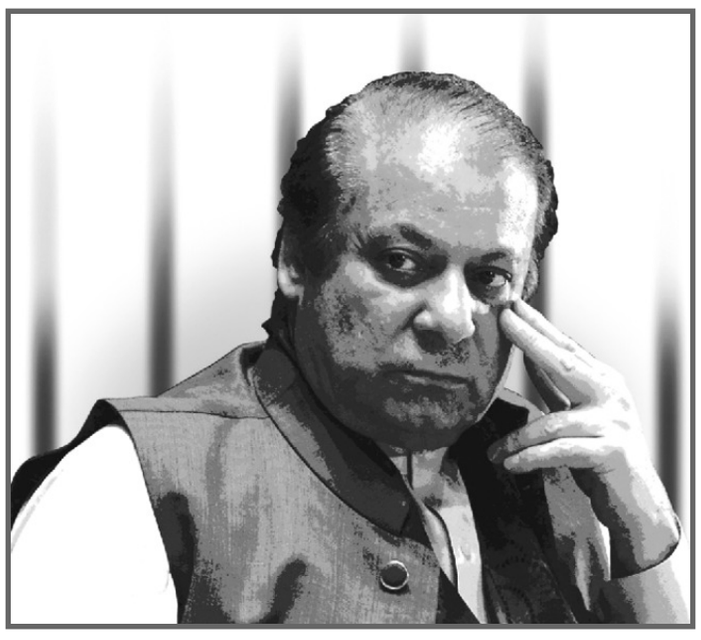

मियां शरीफ के सामने अब दो रास्ते दिखते हैं, या तो वह लंदन में रूप जाएं या फिर पाकिस्तान लौटें , इन दोनों के अपने ही खतरे हैं।

सवाल यह है कि अब नवाज शरीफ के सामने विकल्प क्या हैं? दो रास्ते नजर आते हैं, लेकिन दोनों के अपने-अपने खतरे हैं। एक रास्ता तो यह हो सकता है कि वह अपने मुल्क वापस लौटे ही नहीं। लंदन में ही रुके रहें और वहीं से पाकिस्तान में यह पैगाम देने की कोशिश करें कि उनके साथ ज्यादती हुई है। मगर इस स्थिति में सत्ता छिटकने की आशंका ज्यादा है। दरअसल, 1999 में जब उनकी कुरसी को पलटा गया था, तब वह करीब डेढ़ साल के लिए मुल्क से भाग गए थे। इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा। अगर इस बार भी वह ऐसा कुछ करते हैं, तो लोगों की नजर में 'भगोड़ा' साबित हो जाएंगे। इसका उन्हें सियासी नुकसान होगा। इसमें वह एक उम्मीद की किरण भी देख रहे होंगे, जिसकी वजह खुद इमरान खान हैं। इमरान अस्थिर मिजाज के इंसान माने जाते हैं। अभी उन्हें 'डीप स्टेट' का साथ मिला हुआ है, मगर संभव है कि सत्ता संभालने के एकाध वर्षों में सेना के साथ उनकी तनातनी बढ़े। तब नवाज शरीफ अपने लिए कुछ संभावना देख पाएंगे। संभव है कि उनके पक्ष में फिर से माहौल बने और वह पाकिस्तान वापस लौट सकें। मगर ऐसा नहीं हो पाया और यथास्थिति बनी रही या घरेलू सियासत में तब्दीलियों की वजह से नए खिलाड़ी मैदान में आ गए, तो फिर नवाज के लिए जगह हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। दूसरा रास्ता यह है कि वह हीरो बनकर वापस लौट आएं। चूंकि कुलसुम नाजुक स्थिति में हैं, इसका नवाज को भावनात्मक फायदा मिल सकता है। तब उनकी पार्टी के चुनाव जीतने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। इस स्थिति में उनका जेल में भी रहना कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। मगर इसमें जोखिम यह है कि यदि जनता ने सहानुभूति नहीं दिखाई, तो वह सत्ता से भी दूर होंगे और जेल की हवा भी खाएंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है, जब परवेज मुशर्रफ तानाशाह के रूप में देश के मुखिया थे। तब नवाज शरीफ पूरे जोर-शोर से देश लौटे जरूर, पर उन्हें जनता का भरपूर साथ नहीं मिला। जाहिर है, नवाज शरीफ के सामने एक असमंजस सी स्थिति होगी। वह तमाम सियासी गुणा-भाग कर रहे होंगे। ऐसे में, उनका फैसला क्या होगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। मगर पाकिस्तानी सियासत में उथल-पुथल लाने वाली बिसात बिछ चुकी है। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

प्रसंगवश

मन की व्यथा बांटने में ही सुख

सीताराम गुप्ता

रहीम कहते हैं कि हमें अपने मन की पीड़ा को अपने मन में ही दबाकर रखना चाहिए क्योंकि दूसरे लोग हमारी पीड़ा को सुनकर उसे बांटने की बजाय हमारा उपहास उड़ाते हैं। दूसरों की व्यथा जान-सुनकर उनकी ऐंठ बढ़ जाती थी। यही कारण है कि लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं लेकिन दूसरों पर अपनी व्यथाओं को प्रकट करने का साहस नहीं कर पाते। यदि वास्तव में ऐसा होता तो ठीक था लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। फिर रहीम ने ऐसा क्यों कहा? रहीम ने ये दोहा शताब्दियों पूर्व कहा था। तत्कालीन परिस्थितियां वर्तमान परिस्थितियों से सर्वथा भिन्न थीं। उस समय लोगों पर अधिक मानसिक दबाव नहीं होते थे। लोग बनावटी जीवन नहीं जीते थे और उनका जीवन एक खुली किताब की तरह पारदर्शी होता था।

लोग सीधे-सादे होते थे। उनके जीवन में न तो अधिक इच्छाएं ही होती थीं और न अधिक तनाव ही। आधुनिक मनोविज्ञान भी उस समय विकसित नहीं हुआ था। फिर लोगों पर व्यावहारिकता की बजाय नैतिकता अधिक हावी रहती थी। इसके बावजूद लोग एक-दूसरे का दुख-दर्द समझते थे और बांटने को तैयार रहते थे। हां, कुछ लोग हो सकते हैं जो लोगों के ज़ख्मों पर मरहम लगाने की बजाय उन पर नमक छिड़कने में प्रसन्नता पाते हों। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ये भी सच है कि दूसरों की पीड़ा सुनकर उन्हें राहत पहुंचाने का काम भी दूसरे लोग ही करते हैं। दूसरों की सहायता के बिना हम अपनी व्यथाओं अथवा समस्याओं से मुक्ति नहीं पा सकते।

मनोविश्लेषण के क्षेत्र में आधुनिक शोधकार्यों ने सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति के मन के भावों को ठीक से समझना अनिवार्य है। वैसे भी जब तक कोई रोगी एक चिकित्सक को अपनी शारीरिक दशा से अवगत नहीं कराएगा, उसका सही निदान व उपचार संभव नहीं। मनोभावों के क्षेत्र में तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई मनोरोगी तो अपने विचार सुनाते-सुनाते काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। कई बार कई व्यक्ति किसी अप्रिय स्थिति के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानकर परेशान रहने लगते हैं जबकि वास्तव में उनका दोष नहीं होता। ऐसे में यदि हम अपने मन की बात दूसरों को बतला दें और वो हमें दोषमुक्त कह देता है तो हम सचमुच इस पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। एक दुखी व्यक्ति की बात ध्यानपूर्वक सुनना और उसे उचित सम्मति अथवा सांत्वना देना भी बहुत बड़ी सहायता ही है।

हम अपने जीवन में उन लोगों को सर्वाधिक महत्व देते हैं जो हमारी बातें ध्यान से सुनते हैं और हमें हमारी समस्याओं का समाधान बतलाते हैं। जब तक हम एक दूसरे की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते-सुनाते रहते हैं, हमारे संबंध अच्छे बने रहते हैं। जब हम एक-दूसरे की समस्याओं अथवा व्यथाओं को नज़रअंदाज़ करने लगते हैं तो संबंधों की नींव भी दरकने लगती है। कई बार समस्या का कोई समाधान नहीं होता लेकिन जब तक हम किसी को अपनी समस्या से अवगत नहीं करवा देते अथवा कोई हमारी बात नहीं सुन लेता हम बेचैन रहते हैं। जैसे ही कोई हमारी व्यथा को सुन लेता है हमारा मन हल्का हो जाता है। कई बार हमें स्वयं पता होता है कि हमारी समस्या का कोई हल नहीं लेकिन इसके बावजूद हम अपनी समस्या लोगों को बतलाते हैं और उनकी सम्मति की प्रतीक्षा करते हैं। यदि लोग हमारे प्रति केवल सहानुभूति प्रकट कर देते हैं तो भी हमें असह्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है।

यदि हम अपनी व्यथाओं अथवा समस्याओं को दूसरों से कहने से परहेज करते हैं तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। यही मानसिक पीड़ा अथवा घुटन शारीरिक व्याधियों के रूप में प्रकट होने लगती है। जब हम मानसिक रूप से उद्विग्न अथवा चिंतित होते हैं तो हमारे शरीर में उपस्थित अंत:स्रावी ग्रंथियां उसी अनुपात में शरीर के लिए हानिकारक रसायनों अथवा हार्मोंस का उत्सर्जन प्रारंभ कर देती हैं। आधुनिक युग की अनेक व्याधियां इसी का दुष्परिणाम हैं। यदि कोई हमारी व्यथा को सुन लेता है तो भी वो हमारा उपचार ही कर देता है, चाहे बाद में वो अपने मन में हमारा उपहास ही क्यों न उड़ाए।

दरअसल, हमारे संकोच के कई कारण हो सकते हैं। संभव है इससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचे अथवा हमारा अहंकार चूर-चूर हो जाए। हम अपनी काल्पनिक इमेज को टूटने नहीं देना चाहते। कई बार जब हम अपनी पीड़ा को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वे हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनने की बजाय हमारी कमियां निकालना प्रारंभ कर देते हैं और हमें ही समस्या के लिए दोषी ठहराने लगते हैं। ऐसे में व्यक्ति अपनी व्यथा को दूसरों पर प्रकट करे भी तो कैसे? इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसका व्यथाओं से सामना न होता हो लेकिन हम एक दूसरे को अपने मन की बात कहकर उनकी तात्कालिक पीड़ा व दुष्प्रभाव से मुक्ति अवश्य पा सकते हैं।

पंजाब

नशाखोरी पर नकेल जरूरी

सतीश सिंह

पंजाब में बढ़ते नशे की लत पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2010 से लेकर 2015 में नशे की वजह से पंजाब में 413 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों के अनुसार पंजाब के 50 प्रतिशत नौजवान आज नशे की गिरफ्त में हैं। युवाओं के अलावा पंजाब में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी नशे के जाल में फंसे हुए हैं। बच्चे ड्रग्स नहीं मिलने पर मेडिकल स्टोर से कफ सिरप खरीदकर सेवन कर रहे हैं, जो आसानी से 20-30 रुपये में मिल जाता है। पंजाब में नशे का काला कारोबार अरबों-खरबों रुपये का है। इसी वजह से पंजाब सरकार के लाख दावों के बावजूद नशे का कारोबार और इसके शिकार दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में नशे की वजह से देशभर में 25426 लोगों ने खुदकुशी की है। यानी हर रोज नशे के चलते करीब 7 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि नशे के चलते खुदकुशी करने वालों में बीते 10 सालों में 149 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अखबारों की खबरों के मुताबिक बीते दिनों पंजाब में नशे से 33 दिनों में 46 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद अमरिंदर सरकार हरकत में आई। अखबारों के अनुसार ड्रग्स नहीं मिलने और मिलने के कारण मौतें हो रही हैं। नहीं मिलने पर नशेड़ी अल्कोहल युक्त दवाओं के मिशग्रका सेवन करते हैं, जिसके ओवरडोज से अक्सर लोग मौत के शिकार बन जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों के भी नशे के गिरफ्त में होने की आशंका जताई जा रही है। इसलिए, अमरिंदर सरकार अपने पांच लाख कर्मचारियों का डोप टेस्ट कराकर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कितने सरकारी कर्मचारी नशे के आदी हैं। इसमें पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं के कर्मचारी भी शामिल हैं। सरकारी कर्मचारियों का डोप टेस्ट नियुक्ति, वार्षिक मूल्यांकन और प्रोन्नित के समय कराए जाने की योजना है। दुनिया भर में डोप टेस्ट के 36 सेंटर हैं। लिहाजा, बड़ी संख्या में कर्मचारियों का डोप टेस्ट कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। वर्ष 2016 में अकाली-भाजपा सरकार ने भी भर्ती के समय 7200 सिपाहियों का डोप टेस्ट कराया था। आज एशिया में अफीम का अवैध कारोबार दो क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होता है। पहला, गोल्डन ट्राइएंगल, जिसके तहत म्यांमार, लाओस और दक्षिण चीन के हिस्से आते हैं और दूसरा गोल्डन क्रिसेंट-जिसके अंतर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के देश आते हैं। पंजाब की इन देशों से भौगोलिक नजदीकी ड्रग्स की समस्या की एक बड़ी वजह है। ऐसा भी नहीं है कि पुलिस और खुफिया एजेंसियां ड्रग तस्करी को देख आंखें मूंदे हुए हैं, लेकिन उनके प्रयास नाकाफी हैं। हर साल हजारों करोड़ रुपये के ड्रग्स बरामद किए जा रहे हैं। वर्ष 2011 से 2014 के दौरान पंजाब में 380 लाख किलो ड्रग्स जब्त किए गए थे। नशे पर लगाम लगाने के लिए पंजाब में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 बनाया गया है, जो एनडीपीएस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब में जितने भी कैदी हैं, उनमें से 41 प्रतिशत से अधिक एनडीपीएस एक्ट के तहत कैद हैं। अमरिंदर सरकार ने नशे की लत पर लगाम लगाने के लिये डॉक्टर की पर्ची के बिना सीरिंज बेचने पर रोक लगाई है। माना जाता है कि लोग सीरिंज की मदद से ड्रग्स लेते हैं। सरकार ने ड्रग्स की तस्करी करने वालों को मौत की सजा का भी प्रावधान किया है। इसके लिए पंजाब सरकार की ओर से केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया गया है, लेकिन इस संदर्भ में यह देखना होगा कि यह प्रावधान कितना कारगर है। इस प्रावधान से नशे का नेटवर्क टूट सकता है या नहीं पर गंभीरता से विचार करना होगा। इसके दुरु पयोग से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही, इस प्रावधान के हालात बिहार में शराबबंदी के प्रावधान जैसे होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पंजाब में लोगों के नशे में डूबे रहने के कारण ही ''उड़ता पंजाब' नाम से फिल्म बनाई जा चुकी है, जिसमें नशे के कारोबार में पुलिस-प्रशासन और राजनीति के गठजोड़ की ओर इशारा किया गया है। कहा जा सकता है पंजाब में नशे के बढ़ती लत को रोकने के लिए सरकार को व्यावहारिक कदम उठाने होंगे। हालांकि, सरकार ने इस पर नकेल कसने के लिए हरसंभव प्रयास किएहैं, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। हां, जागरूकता कार्यक्रम के जरिये इस पर काबू पाया जा सकता है। सरकार को भ्रष्टाचार पर भी सख्ती दिखानी होगी। भ्रष्टाचार कई सारी समस्याओं की जड़ है।

संक्षिप्त समाचार

चारबाग में प्लेटफार्म पर लगी आग

लखनऊ । चारबाग स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार पर आग लग गई। सुरक्षा उपकरण न होने के कारण नालियों में बह रहे डीजल में लगी आग धीरे-धीरे बढ़ने लगी, इससे अफरातफरी मच गई। स्टेशन पर नए फुट ओवर ब्रिज के लिए गर्डर रखने थे। इसलिए प्लेटफार्म नंबर चार पर गर्डर में वेल्डिंग का काम होना था। 1 सुबह करीब नौ बजे के आसपास कर्मी तैयारी में जुट गए। लेकिन, वेल्डिंग काम से पहले वहां बनी नालियों को नहीं ढका गया। इसके चलते वेल्डिंग के समय नालियों में बहने वाले डीजल में चिंगारी गिरने से आग लग गई। आग लगने की सूचना रेलवे अधिकारियों को मिलती इससे पहले कर्मियों ने पानी डाल कर आग बुझाने का प्रयास किया। इससे आग बढ़ गई। आनन-फानन इसकी सूचना रेलवे अधिकारियों समेत स्टेशन निदेशक को दी गई। आरपीएफ और जीआरपी स्टाफ भी मौके पर पहुंचा। 1 स्टेशन निदेशक के निर्देशानुसार प्लेटफार्म पर लगे फल के ठेले और स्टाल कर्मियों के पास से अग्निशमन यंत्र लेकर आग पर काबू पाया। लगभग डेढ़ घंटे बाद डीजल में लगी आग को बुझाया जा सका। इसके बाद कर्मियों ने नालियों को ढककर काम शुरू किया।

तीन सरकारी विभागों को लार्वा मिलने पर नोटिस

लखनऊ। एंटी लार्वा अभियान के तहत क्रॉस चेकिंग के दौरान लार्वा पाए जाने पर मलेरिया विभाग ने तीन सरकारी विभागों को नोटिस जारी किया है। शनिवार को मलेरिया विभाग की ओर से किए गए औचक निरीक्षण के दौरान राजधानी के विकास भवन, जिला विकास अधिकारी व सहकारिता विभाग के दफ्तर में लार्वा पाए गए। 1मलेरिया अधिकारी डीएन शुक्ला ने बताया कि तीनों विभागों को नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर मौके से लार्वा नष्ट कराने के साथ वहां पानी को सुखाने व साफ-सफाई का निर्देश जारी किया गया है। इस दौरान लार्वा नष्ट नहीं कराए जाते हैं तो जुर्माना भी लगाया जाएगा। कहा कि संचारी रोग नियंत्रण माह के तहत वेक्टर जनित रोगों के खिलाफ मलेरिया विभाग लगातार अभियान चला रहा है। इसी के तहत चिनहट में तीन स्कूलों के छात्रों के साथ जनजागरूकता रैली भी निकाली गई। पोस्टर बैनर के जरिये व बातचीत कर लोगों को अपने आसपास पानी नहीं जमने देने व मच्छर से बचने के उपाय सुझाए गए। ताकि डेंगू-मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। 1उन्होंने कहा कि मलेरिया विभाग का क्रॉस चेकिंग अभियान जारी रहेगा। इस दौरान विभिन्न सरकारी व निजी दफ्तरों के अलावा घरों में कूलर इत्यादि की भी जांच की जाएगी। अगर कहीं लार्वा मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

जैसी ग्रेडिंग, वैसी फीस

लखनऊ । निजी आइटीआइ में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही अब मनमानी फीस को लेकर लगाम लगाने की कवायद शुरू हो गई है। संस्थाओं की जैसी ग्रेडिंग होगी, वैसी ही फीस का निर्धारण किया जाएगा। राजधानी समेत प्रदेश में 2611 आइटीआइ संस्थाओं के दो लाख छात्रों को अभी चल ही रही थी कि फीस निर्धारण को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सोमवार को एक बार फिर फीस निर्धारण को लेकर अधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें फीस को लेकर मंथन होगा।1पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट की भांति व्यवसायिक परीक्षा परिषद की प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से आइटीआइ में भी प्रवेश होंगे। फीस निर्धारण के लिए पहले संस्थाओं के प्रबंधकों को अपनी ग्रेडिंग करानी होगी, इसके बाद फीस का निर्धारण होगा। शुल्क प्रतिपूर्ति के लाभ के लिए सितंबर तक फीस निर्धारण की चुनौती भी विभाग के सामने मुंह बाए खड़ी है। राजधानी की 40 समेत प्रदेश की सभी 2611 निजी संस्थाओं की ओर से ली जाने वाली मनमानी फीस पर शिकंजा लगाने के क्रम में ग्रेडिंग चल रही है। अभी तक एक हजार संस्थाओं की ग्रेडिंग की गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से वर्ष 2014 में निजी आइटीआइ संस्थाओं की फीस का निर्धारण किया गया था।

नीतीश को खटकी गिरिराज की ये बात, कहा- बख्शे नहीं जाएंगे ऐसे लोग

पटना । जनता दल यूनाइटेड (जदयू) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रविवार को नीतीश कुमार के निशाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रहे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले को छोड़ा नहींजाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गिरिराज सिंह का नाम लिए बगैर नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के एक मंत्री जेल में जाकर दंगे के आरोपित से मुलाक़ात कर रहे हैं।केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की नवादा जेल में दंगा के आरोपित से मुलाक़ात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खटक गई है। रविवार को दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार न किसी को बचाती हैं और ना फंसाती है। लेकिन ऐसा धंधा करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे।कार्यकारिणी की बैठक के बाद जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने तो गिरिराज सिंह का नाम लेकर उनकी निंदा की। नवादा में सांप्रदायिक घटना की चर्चा करते हुए कहा कि मंत्री जेल जाकर दंगे के आरोपित से मिलते हैं। किसी मंत्री का बिहार की व्यवस्था पर सवाल उठाना तथा आरोपितों से सहानुभूति दिखाना, उनसे मिलना उचित नहीं है।कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने पुरानी बात दोहरायी कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार, अपराध और सांप्रदयिकता से समझौता नहीं करेगी, चाहे सरकार रहे या चली जाए। नीतीश कुमार की बातों से साफ है कि वे सांप्रदायिकता के मुद्दे पर निबटने में नरमी नहीं बरतने वाले, भले ही सरकार चली जाए।

पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल साइट पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार

इलाहाबाद । सोशल साइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद अभद्र टिप्पणी करने के मामले में संगमनगरी के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस युवक ने फेसबुक पर प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की थी।इलाहाबाद के खीरी थाना अन्तर्गत ग्राम डीही के पंकज शुक्ला पुत्र शैलेष शुक्ला ने बीती सात जुलाई को फेसबुक पर प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी फेसबुक पर पोस्ट की थी। इसके बाद यह पोस्ट वायरल होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित पंकज को गिरफ्तार कर लिया।इस मामले में पंकज का कहना है कि सात जून को साथियों के साथ मेड़ पर मोबाइल रखकर क्रिकेट खेल रहा था। वहां से गांव में एक दावत में चला गया। वहां पर ही ध्यान आया कि मेरा मोबाइल क्रिकेट स्थल पर छूट गया है। वापस आया तो मोबाइल वहीं मिल गया। कुछ देर बाद देखा तो किसी ने मेरे मोबाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट कर दिया था। उसे फौरन डिलीट कर दिया।आरोपी युवक ने बताया कि वह एलएलबी का छात्र है। पिता मुम्बई मे सिक्योरिटी गार्ड हैं। थानाध्यक्ष वेदप्रकाश पांडेय ने बताया कि पूरे घटना के सम्बन्ध मे आलाअधिकारियो को जानकारी है।

बाढ़ का एक इफेक्ट यह भी: नहीं आया दूल्हा तो शादी करने दुल्हन जा पहुंची ससुराल

कटिहार । बिहार में बाढ़ जो न कराए। बाढ़ का पानी नदी में चढ़ने के कारण गंगा नदी में फेरी सेवा बंद कर दी गई। इसका असर शादियों पर भी पड़ा। ऐसा ही एक मामला कटिहार में सामने आया, जिसमें बारात नहीं आ पाने के कारण दुल्हन ही शादी करने दूल्हा के घर गई।जानकारी के अनुसार बाढ़ के कारण मनिहारी व साहेबगंज के बीच गंगा नदी में फेरी सेवा बंद कर दी गई है। यहां नौ परिवहन ही यातायात का मुख्य साधन रहने के कारण इलाके में बारात का आना-जाना प्रभावित हो गया है। इस कारण रविवार को एक दुल्हन अपने परिवार के साथ नाव से ब्याह रचाने दूल्हे के घर खाना हुई।

डॉ. महमूद हुसैन रहमानी- अंधेरी जिंदगियों को रोशन करने का जुनून

कानपुर, 9 जुलाई

दुनिया के रंग आंखों से ही देखे जाते हैं, अगर किसी के नेत्र में ज्योति नहीं है। तो उसके लिए यह संसार एक अंधेरे कुएं की तरह है। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि समय से नहीं मिल पाने वाले साधारण इलाज के चलते अपनी आंखों की रोशनी से महरूम हो जाते हैं। इसी जरूरत को समझा कानपुर के डॉ. महमूद हुसैन रहमानी ने।

कानपुर के डॉ. रहमानी देशभर में नेत्रहीनों (कॉर्नियल ब्लाइंड) के लिए रोशनी की एक किरण हैं। वह तमाम जरूरतमंदों को आंखों का नूर देकर उस परिभाषा को साकार कर चुके हैं कि डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं। 1989 से नेत्रदान महादान अभियान चला रहे एम्पायर एस्टेट निवासी डॉ. रहमानी अब तक 1034 नेत्रहीनों का निशुल्क कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर उनकी जिंदगी में उजाले की खुशियां भर चुके हैं।नवीन मार्केट स्थित सोमदत्त प्लाजा में गॉड सर्विस आई क्लीनिक चलाने वाले डॉ. महमूद हुसैन रहमानी शिफा आई रिसर्च सेंटर के नाम से चमनगंज में तीस बेड का अस्पताल चला रहे हैं। नेत्रदान महादान अभियान चलाकर डॉ. रहमानी यह भरोसा जुटाने में भी कामयाब रहे हैं कि जो भी मृत्योपरांत नेत्रदान करना चाहे, वह किसी सरकार या संस्था से संपर्क की बजाए इन्हें कॉल करता है। इनके पास दान के कॉर्निया आते हैं, जिन्हें वह पंजीकरण करा चुके नेत्रहीनों में ट्रांसप्लांट कर देते हैं।आजाद हिंद फौज में महिला विंग की कमांडर रहीं कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने भी डॉ. रहमानी के मार्फत ही मृत्योपरांत नेत्रदान किया था। डॉ. रहमानी बताते हैं कि निजी अस्पताल में कॉर्निया ट्रांसप्लांट पर एक से डेढ़ लाख रुपये खर्च आता है। मगर, वह एक पैसा भी मरीज से नहीं लेते। दस दिन में दवाई आदि पर होने वाला 30 से 35 हजार रुपये का खर्च वह खुद वहन करते हैं। इसके बाद नेत्रदाता के नाम पर परिजनों को अमर ज्योति सम्मान भी देते हैं। उनकी बड़ी बेटी डॉ. अर्शिया रहमानी और भतीजा डॉ. जिया उर रहमान भी नेत्र सर्जन हैं, जो इस सेवा कार्य में उनके साथ जुटे हुए हैं।डॉ. रहमानी कहते हैं कि सरकार को नेत्रदान और कॉर्निया ट्रांसप्लांट को गंभीरता से लेना चाहिए। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाने चाहिए। इसके साथ ही नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए योजना बने। जो भी कॉर्निया दान करने के लिए पंजीकरण करा ले, उसे आई डोनेटर का कार्ड जारी कर सरकारी अस्पतालों में उसे इलाज में रियायत दी जाए।

बर्रा में फैब्रिकेशन का कारखाना चलाने वाले कल्लू विश्वकर्मा डॉ. रहमानी को भगवान का ही दर्जा देते हैं। इसके पीछे वजह भी उतनी बड़ी है। कल्लू ने बताया कि उनकी एक आंख बचपन से खराब थी। धीरे-धीरे दूसरी आंख से भी दिखना बंद हो गया। तब उन्हें किसी से डॉ. रहमानी के बारे में पता चला तो उनसे संपर्क किया।डॉ. रहमानी ने जांच में पाया कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से रोशनी आ जाएगी। 14 अक्टूबर 2014 को ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद जिंदगी सामान्य हो गई। मगर, तीन साल बाद बाइक चलाते समय उसी आंख में तिनका चला गया। मवाद पड़ने से आंख से दिखना फिर बंद हो गया। उसके बाद तो कारखाना कारीगरों के भरोसे छोड़ना पड़ा। कहीं आने-जाने के लिए परिचितों की मदद लेनी पड़ती थी। दोबारा डॉ. रहमानी से संपर्क किया तो एक दिसंबर 2017 को फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर उन्होंने रोशनी दे दी।डॉ. महमूद हुसैन रहमानी ने बताया कि 80 के दशक में जब उन्होंने पढ़ाई पूरी की, तब भी देश में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का आंकड़ा 35 से 40 लाख था। उसके बाद से नेत्रदान महादान का सरकारी अभियान तो चलता रहा, लेकिन अब तक लोग उतने जागरूक नहीं हुए। कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी उतने नहीं हो रहे। यही वजह है कि अभी आंकड़ा 35-40 लाख के बीच ही है।

दस साल में अरबपति बन गया सटोरिया

सफेदपोश और अफसरों के संरक्षण से बढ़ रहा था काला कारोबार, पंद्रह साल से कर रहा है सट्टे का धंधा दो साल पूर्व गया था पहली बार जेल

आगरा। पुलिस की चेकिंग में पकड़ा गया शहर का सबसे बड़ा सटोरिया श्याम बोहरा दस साल पहले सामान्य व्यक्ति था। स्कूटर पर चलता था और दवा का अवैध कारोबार करता था। मगर, एक दशक में ही वह अरबपति बन गया। महंगी लग्जरी कारों से चलने वाले सटोरिये का कारोबार बढ़ने के पीछे सफेदपोश और अफसरों का संरक्षण माना जा रहा है। 1ताजगंज के पारसनाथ पंचवटी में रहने वाला श्याम बोहरा पुत्र श्रीराम बोहरा पंद्रह साल से सट्टे का काला कारोबार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक, दस साल पहले वह दवा का अवैध कारोबार करता था और स्कूटर से चलता था। वर्ष 2008 तक उसे ताजगंज के एक स्थानीय नेता का संरक्षण था। उसके माध्यम से एक माननीय से संबंध बनाए और बड़े स्तर पर कारोबार शुरू कर दिया। 2009 में पहली बार उसका सट्टे में नाम सामने आया। मगर, पुलिस ने उसे बचा दिया। कुछ ही दिन में वह शहर का सबसे बड़ा बुकी बन गया और ऑडी कार से चलने लगा। सफेदपोशों और अफसरों के संरक्षण के चलते उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद फरवरी 2017 में पहली बार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा। ताजगंज थाने में धोखाधड़ी और 13 जुआ एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। चार दिन बाद जमानत पर वह जेल से बाहर आ गया।

इसमें पुलिस ने मई 2017 में केवल 3 /4 जुआ अधिनियम में चार्जशीट लगाकर काम खत्म कर दिया। इसमें श्याम बोहरा के साथी जिप्पी और शैलेष अग्रवाल उर्फ निक्की के नाम निकाल दिए गए। इसके बाद फिर खुलेआम खेल चल रहा था। चर्चाएं हैं कि अब उसकी पैरवी शहर के एक बड़े कारोबारी द्वारा की जा रही है। कारोबारी की अफसरों से करीबी के चलते 2017 में सटोरिये को पकड़ने वाली पुलिस टीम पर गाज गिर गई।

बदालीखेड़ा में निर्माण के साथ उखड़ने लगी नाली

लखनऊ । एक तो लंबे समय बाद विकास की आस जगी तो अभियंताओं और ठेकेदारों की मनमानी से हर कोई परेशान है। कानपुर रोड के बदाली खेड़ा में सड़क व नाली निर्माणों में मानकों की अनदेखी हो रही है। तीन माह पहले बनी सड़क में गड्ढे हो गए तो बनने के साथ ही नाली टूटने लगी है। सांसद निधि से यह निर्माण लोक निर्माण विभाग करा रहा है। बदाली खेड़ा के निवासियों ने घटिया निर्माण का विरोध जताया तो ठेकेदार के लोगों ने धमका दिया। कि नाली निर्माण में लगाई गईं ईंट उखड़ रही है।

करीब दस फीट में तो नाली बैठ गई है। बदाली खेड़ा निवासी दया और जयप्रकाश सिंह व अन्य का कहना था कि तीन माह पहले बनाई सड़क उखड़ गई है। सड़क निर्माण के समय ही हर किसी ने पतली लेयर बिछाने का विरोध किया था, लेकिन अभियंताओं और ठेकेदारों ने नहीं माने। इसी तरह नाली में इतनी घटिया निर्माण सामग्री लगाई जा रही है कि ईंट उखड़ रही है। बदाली खेड़ा के निवासियों ने हाथ से ही ईंट को उखाड़कर दिखाया।

मेरठ में हृदय रोगियों की बढ़ती संख्या है चिंता का विषय

लखनऊ। विकसित होते शहर आज बीमारी के अड्डे बनते जा रहे हैं। हमारी लाइफस्टाइल में आते बदलाव के कारण व्यक्ति के हृदय पर बुरा असर पड़ रहा है और दिल से संबंधित तमाम बीमारियां दिन पर दिन सामने आ रही हैं। अब दिल की बीमारी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को अपना शिकार बना रही है।

ऐसे समय में मेरठ के वरिष्ठ काडियोलॉजिस्ट डॉ. राजीव अग्रवाल पिछले 16 वर्ष में 450 से ज्यादा गरीब मरीजों को पेसमेकर नि:शुल्क लगाकर जीवनदान दे चुके हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले डीएम कार्डियोलाजिस्ट हैं, जिन्होंने मेरठ जैसे छोटे शहर को इलाज की गुणवत्ता के मामले में राष्ट्रीय स्तर का रुतबा दिया। दुनिया भर की कॉन्फ्रेंस में उन्हें बड़े चाव से सुना जाता है। डॉ. अग्रवाल नए हृदय रोग विशेषज्ञों के आइकॉन हैं।मेरठ निवासी 57 वर्षीय डॉ. राजीव अग्रवाल ने भारत में सर्वाधिक नि:शुल्क पेसमेकर लगाने का रिकॉर्ड बनाया। यूएसए की बोस्टन कार्डियक फाउंडेशन के साथ मिलकर वह हर वर्ष पेसमेकर कैंप लगाते हैं, जिसमें देशभर से मरीज पहुंचते हैं। नि:शुल्क पेसमेकर के लिए सालभर पंजीकरण चलता है।असर ये हुआ कि मेरठ के दर्जनभर परिवार नि:शुल्क पेसमेकर कैंप में आर्थिक सहयोग के लिए खड़े हुए।

ऐसी भी क्या नींद..

नींद हमारे जीवन में उतनी ही जरूरी है जितना कि खाना। लेकिन यह नींद हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। रविवार देर रात चारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में भीड़ होने के कारण गेट पर सोते ये लोग। ' उमेश शुक्ला

बिहार में भीड़ ने फिर हाथ में लिया कानून; दो लुटेरों को पकड़कर पीटा, एक की मौत

सिवान । बिहार के इन दिनों भीड़ के कानून हाथ में लेकर हत?याएं करने या इसकी कोशिश की कई घटनाएं सामने आई हैं। बीते दिन नालंदा में एक हत?यारे को पीट-पीटकर मार डालने की कोशिश के बाद रविवार को भी ऐसी घटना सामने आई। सिवान में भीड़ ने दो लुटेरों को जमकर पीटा, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई।सिवान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्यामपुर बाजार में रविवार की दोपहर तीन बजे बाइक सवार हथियारबंद छह अपराधियों ने एक सोना-चांदी की दुकान में लूटपाट की तथा घटना के दौरान दुकानदार अजय कुमार उर्फ टुनटुन सोनार पर फायरिंग कर उन्हें घायल कर दिया।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, दो वर्ष में सूबे के दो करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार

मुरादाबाद । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पीतलनगरी में बड़ी उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां सर्किट हाउस में निर्यातकों और शिल्पकारों से एक जनपद एक उत्पाद योजना पर किया सीधा संवाद किया। इसके बाद उनकी समस्या भी पूछने के बाद निदान का आश्वासन दिया।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से निर्यातकों व दस्तकारों में नई उम्मीद जगी है। उन्होंने एक जनपद एक उत्पाद पर निर्यातकों एवं शिल्पकारों से सीधा संवाद किया। कहा कि एक जनपद एक उत्पाद योजना (ओडीओपी) के माध्यम से दो वर्ष में प्रदेश के दो करोड़ युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। ओडीओपी से प्रदेश के परंपरागत उद्योगों को नया रूप देकर प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय जगत पर चमकाएंगे।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसके साथ हम प्रदेश दस करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।इससे पहले आज शाम मुख्यमंत्री का हेलीकाप्टर ने सर्किट हाउस प्रांगण में उतरने से पहले शहर का चक्कर लगाया। भाजपाइयों और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद सीधे सभागार में पहुंचे। दस्तकारों और निर्यातकों से परिचय करने के बाद उन सभी से अपनी-अपनी बात रखने के लिए कहा।सभी की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने जो समस्याएं उठाई हैं। वह जायज हैं और उनका निस्तारण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। अगस्त में एक जनपद एक उत्पाद योजना को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक होने जा रही है। प्रदेश भर से उद्यमियों को आमंत्रित किया जाएगा।भाजपा जिला व महानगर पदाधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आप भी जनता की समस्याओं के निस्तारण में सहयोग करें।

मुंबई में इलाज करा पटना लौटे लालू यादव, डॉक्टरों ने दी है आराम की सलाह

पटना । राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रविवार को मुंबई में इलाज कराकर पटना लौटे। चारा घोटाला के कई मामलों में सजायाफ्ता लालू फिलहाल बीमारी की वजह से इलाज कराने के लिए ही प्रोविजनल बेल पर जेल से बाहर हैं। लालू के साथ उनकी बेटी व राज्यसभा सांसद मीसा भारती तथा राजद नेता भोला यादव भी थे।

लालू प्रसाद यादव अपने इलाज के लिए मुंबई के एशियन हॉस्पिटल में 17 जून से भर्ती थे। वहां 24 जून को उनका फिस्टुला का ऑपरेशन हुआ था। इसके पहले वे इलाज के लिए मुंबई और बेंगलुरु भी गये थे। एशियन हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उन्हें तीन महीने तक आराम करने की सलाह दी है।

इलाज के बाद वे रविवार को अपराह्न काल में बेटी मीसा भारती तथा सहयोगी राजद नेता भोला यादव के साथ फ्लाइट से पटना पहुंचे। भोला यादव ने बताया कि लालू का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। उन्हें फिलहाल आराम की जरूरत है।

विदित हो कि चारा घोटाले मामले में सजा पाए लालू प्रसाद यादव की बेल अवधि रांची हाई कोर्ट ने बढ़ाकर तीन जुलाई कर दी थी। इसके पहले बीमारी की वजह से लालू को 11 मई से छह सप्ताह की जमानत मिली थी। रांची हाई कोर्ट ने लालू की बेल फिर छह सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है।

नीतीश के नाम पर एक हुआ महागठबंधन

पटना । जनता दल यूनाइटेड (जदयू) को महागठबंधन में शामिल करने को लेकर कांग्रेस ने अपने स्टैंड को साफ कर दिया है। कल तक जदयू का स्वागत करती कांग्रेस ने अब यू-टर्न लेते हुए कहा है कि नीतीश कुमार के लिए कांग्रेस में 'नो एंट्री' है। इसके पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने पहले ही महागठबंधन में नीतीश कुमार के लिए 'नो एंट्री' का बोर्ड लगा रखा है।

विदित हो कि कांग्रेस ने यह फैसला राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर जदयू के बयान के बाद लिया है। जदयू ने महागठबंधन छोड़ने के कारण की चर्चा करते हुए इसके लिए कांग्रेस द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर साथ नहीं मिलना भी बताया था। साथ में यह भी कहा था कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के भ्रष्टचार कु मुद्दे पर राहुल गांधी से मुलाकात की थी, लेकिन राहुल गांधी ने उदासीनता बरती।दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा था कि बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल सहित कई नेताओं ने नीतीश कुमार से महागठबंधन में शामिल होने की अपील की है। लेकिन, कांग्रेस जब तक राष्ट्रीय जनता दल (राजद) जैसे भ्रष्ट दल के साथ कांग्रेस अपना स्टैंड साफ नहीं करती, यह संभव नहीं है।अब बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उन्होंने कभी भी नीतीश कुमार से महागठबंधन में शामिल होने का आग्रह नहीं किया। लालू प्रसाद यादव के संबंध में गोहिल ने कहा कि राजद को लेकर कांग्रेस का स्टैंड बिलकुल साफ है। कांग्रेस को इसपर दोबारा विचार करने की कोई जरूरत नहीं है।गोहिल ने कहा कि नीतीश कुमार का महागठबंधन में स्वागत नहीं है। वे कांग्रेस को सुझाव देने के बदले आत्मविश्लेषण करें। विचार करें कि उन्होंने अपनी क्या स्थिति कर ली है।कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि महागठबंधन तोड़ने के लिए नीतीश कुमार कांग्रेस को दोष न दें। नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर जाने का मन बना चुके थे, वे केवल बहाना खोज रहे थे।

प्रियंका ने कहा कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को वोट दिया था। चुनाव में राजद को जदयू से अधिक सीटें मिलीं थीं। ऐसी हालत में नीतीश कुमार द्वारा गठबंधन तोड़कर विपक्षी गठबंधन (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) हाथ मिलाना जनमत अपमान था। नीतीश कुमार से इसका हिसाब जनता आगामी चुनावों में लेगी।

सूरत। वनिता विश्राम विमेन्स कॉलेज ऑफ कोमर्स में 21वें स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में कॉलेज की गर्लस ने बढचढ कर भाग लिया जिसमें 50 युनिट रक्त एकत्रित किया गया।

भाजपा के पूर्व विधायक कनु कलसरिया को कांग्रेस में लाने की कवायद तेज

अहमदाबाद। महुवा के पूर्व विधायक डॉ. कनुभाई कलसरिया को कांग्रेस में लाने की कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद भाजपा के पूर्व विधायक डॉ. कलसरिया कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। सौराष्ट्र में कोली समाज के बड़े नेता कुंवरजी बावलिया के भाजपा में शामिल हो गए हैं और उन्हें मंत्री पद भी मिल गया है। अब कांग्रेस को सौराष्ट्र में दिग्गज नेता की तलाश है और तलाश डॉ. कलसरिया पर पूरी होती नजर आ रही है। हांलाकि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले डॉ. कलसरिया कांग्रेस में शामिल होनेवाले थे। परंतु किन्हीं कारणों से यह संभव नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और डॉ. कलसरिया पिछले कई दिनों से एक-दूसरे के संपर्क में हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आगामी 16 जुलाई से गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और उसी वक्त डॉ. कलसरिया के कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया जा सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले डॉ. कनुभाई कलसरिया का कांग्रेस में प्रवेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में डॉ. कलसरिया को उ मीदवार बना सकती है। ईमानदार और सेवाभावी डॉक्टर व नेता की छवि वाले डॉ. कलसरिया जब भाजपा के विधायक थे, तब अपनी ही निरमा के खिलाफ आंदोलन किया था। हांलाकि उस आंदोलन को कांग्रेस और भाजपा से कोई सहयोग नहीं मिला था।

सूरत जिला में 16 जुलाई से ओरी और रुबेला टीकाकरण अभियान अंतर्गत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित

सूरत, 9 जुलाई। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 तक ओरी नाबूद करने तथा रुबेला/जन्मजात रूबेला सिन्ड्रोम पर नियंत्रण लगाने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत राज्य में मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान शुरु किया गया है। सूरत जिला में अभियान 16 जुलाई 2018 से शुरु होगा। जिसमें 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को सम्मिलित किया जायेगा।

ओरी और रुबेला टीकाकरण अभियान को वेग देने के लिए डिस्ट्रीक्ट हेल्थ सोसायटी, स्वास्थ्य शाखा जिला पंचायत, सूरत द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय के सभाखंड में जिला कलेक्टर धवल पटेल की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में कलेक्टर ने कहा कि एक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत ओरी और रूबेला के खिलाफ सुरक्षा देने के लिए ओरी-रूबेला (एम.आर.) का टीका शालाओं और आउट रीच में दिया जायेगा। 16 जुलाई 2018 से समग्र राज्य में तथा सूरत जिला में शुरु होनेवाले इस अभियान में जिला के 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को यह टीका लगाया जायेगा। जिला का एक भी बच्चा इस टीके से वंचित न रह जाये इसके आवश्यक सहयोग देने हेतु जिला की प्रजा को जिला प्रशासनतंत्र द्वारा अनुरोध किया गया है।

16 जलाई से पांच सप्ताह के लिए ओरी-रूबेला टीकाकरण अभियान में सूरत जिला में 9 माह से 15 वर्ष तक के कुल 4,74,411 बच्चों को समावेहित करने का लक्ष्यांक रखा गया है। शाला में जानेवाले तथा न जानेवाले बच्चों को शामिल किया जायेगा। यह कार्यवाही पूर्ण करने के लिए 57 पीएससी और चार सामूहिक स्वास्थ्य केन्द्र मिलाकर कुल 61 केन्द्रों तथआ जिला की 1638 नर्सरी शाला, नीजी शाला, आश्रम शाला, आंगनवाडी केन्द्रों को शामिल किया जायेगा। जिसमें दो सप्ताह स्कूल में, दो सप्ताह आंगनवाडी में तथा पिछले सप्ताह में बाकी रह गये तथा छुट गये बच्चों को समावेहित किये जाने का कार्य किया जायेगा। ओरी और रुबेला टीकाकरण संपूर्ण रुप से सुरक्षित है और उसकी कोई दुष्प्रभाव नहीं है। हमारे गांव की शाला, आंगनवाडी, स्वास्थ्य केन्द्र में जब ओरी और रुबेला का टीकाकरण कार्यक्रम जिस दिन हो उस समय इस कार्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग देने के लिए सभी से अपील की गई है। डब्ल्युएचओ के डॉ. चिराग वलीया ने जानकारी देते हुये कहा कि भारत के 16 राज्य के आठ करोड बच्चों का टीकाकरण करके अभियान को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। गुजरात में इस अभियान को 100 प्रतिशत सफलता मिले ऐसा ध्येय रखा गया है। इस अभियान के तहत जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरु की गई कार्यवाही की जानकारी दी। ओरी एक जानलेवा रोग है जो वायरस से फैलता है। बच्चों में ओरी के कारण विकलांगता और अकाल मौत होने की संभावना रहती है। रुबेला एक संक्रामक रोग है जो वायरस से फैलता है। सिके लक्षण ओरी जैसे ही दिखाई दे सकते हैं। वह लडके और लडकियों दोनों को ग्रसित कर सकता है। यदि कोई महिला गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में उससे संक्रमित होती है तो कंजेनिटल रुबेला सिन्ड्रोम (सीआरसी) हो सकती है। जो उसके गर्भ व नवजात शिशु के लिए घातक हो सकता है। भारत में प्रति वर्ष 50,000 से अधिक बच्चों की ओरी के कारण मृत्यु होती है। जिससे सभी अभियान में सहयोग देकर टीका लेने की हिमायत करे ऐसी उन्होंने अपील की। इस मीटिंग में मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. हसमुख चौधरी, जिला शिक्षाधिकारी यु.एन. राठोड, जिला प्राथमिक शिक्षाधिकारी खराडी, पीडीयाट्रीक एसोसियेशन के प्रमुख प्रशांत कारीया, सेक्रेटरी हितेश शिंदे, मेडिकल कॉलेज के डॉ. महुवा मोइत्र, डॉ. जीगिशाबेन, लायन्स कल्ब के प्रतिनिधि, तमाम तहसील के स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहे।

रथयात्रा में सुरक्षा व्यवस्था की पूर्व तैयारियों की गृह मंत्री ने की समीक्षा

14 जुलाई को अहमदाबाद समेत राज्यभर में 164 रथयात्रा-शोभायात्राएं निकलेंगी

अहमदाबाद (ईएमएस)। 14 जुलाई को शहर समेत राज्यभर में निकलने वाली भगवान जगन्नाथजी की 164 रथयात्रा एवं शोभायात्रा शांतिपूर्ण माहौल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह है। गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने आज रथयात्रा पर सुरक्षा व्यवस्था की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। प्रदीपसिंह जाडेजा ने कहा कि रथयात्रा देशभर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है और राज्यभर में 164 जितनी रथयात्रा और शोभायात्रा शांति और श्रद्धापूर्ण माहौल में संपन्न कराने को गृह विभाग सज्ज है। 14 जुलाई को राज्यभर में निकलनेवाली रथयात्रा एवं शोभायात्रा के संदर्भ में आज गांधीनगर में कानून-व्यवस्था की स्थिति की सर्वग्राही समीक्षा करते हुए जाडेजा ने काह कि शहर समेत राज्य के 33 जिलों में 164 जितनी रथयात्रा-शोभायात्रा निकलती हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सीधे मार्गदर्शन में गृह विभाग ने विशेष तौर पर पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त का आयोजन किया है। रथयात्रा के दौरान किसी भी अनिच्छनीय घटना से निपटने और सौंप्रदायिक सौहार्द का माहौल बरकरार रखने के लिए हरसंभव उपाय किए गए हैं। अहमदाबाद समेत राज्यभर में निकलनेवाली रथयात्रा का राज्यस्तर पर लगातार मोनिटरींग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल भगवान जगन्नाथजी की 11। और अन्य देवी-देवताओं की 4। समेत कुल 164 रथयात्रा और शोभायात्राएं निकलेंगी। जिसमें 15 जिलों की 18 रथयात्रा संवेदनशील हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। इन रथयात्राओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। संवेदनशील इलाकों में निकलने वाली रथयात्रा के लिए एसपी, डीवायएसपी स्तर के अधिकारियों को नियुक्त कर पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। भावनगर जिले में कुल 11 जितनी रथयात्रा निकलेगी और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी 1 आईजी/डीआईडी, 1 एसपी, 15 डीवायएसपी, 36 पीआई, 110 पीएसआई स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार आणंद जिले में 15 रथयात्रा के लिए 1 आईजी/डीआईजी, 1 एसपी, 6 डीवायएसपी, 19 पीआई, 66 पीएसआई और वडोदरा शहर में होनेवाली रथयात्रा की सुरक्षा के जिम्मेदारी 10 पीआई और 20 पीएसआई स्तर के अधिकारियों की सौंपी गई है। इसके अलावा राज्य में 1। जितनी एसआरपीएफ की कंपनियां स्टेन्डबाय रहेंगी, आकस्मिक संजोगों में राज्य के पुलिस महानिदेशक द्वारा आवंटित की जाएंगी।

पुलिस का घर भी सुरक्षित नहीं, डीवायएसपी के घर से 20 के जेवरों की चोरी

अहमदाबाद (ईएमएस)। शहर के नारोल क्षेत्र में महिला पुलिस उपाधीक्षक के घर से रु. 20 लाख के आभूषणों की चोरी की घटना के पुलिस बेडे में हड़कम्प मच गया है। डीवायएसपी की शिकायत पर नारोल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। अहमदाबाद में आगामी 14 जुलाई को निकलनेवाली भगवान जगन्नाथजी की रथयात्रा को लेकर शहरभर में पुलिस लगातार गश्त कर रही है, लेकिन चोरों में जैसे कोई खौफ नहीं हो, इस प्रकार एक पुलिस अधिकारी के घर में हाथ साफ कर पुलिस को चुनौती दे दी। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद के नारोल क्षेत्र के भगीरथ होम्स बंगला निवासी और जूनागढ़ की पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में सेवारत पुलिस उपाधीक्षक चेतना नवीनचंद्र चौधरी ने नारोल पुलिस थाने में 6। तोला सोने के आभूषण चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई है। जूनागढ़ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में ड्यूटी होने से चेतना चौधरी जूनागढ़ में ही रहती हैं। बीते दिन चेतना चौधरी को फोन पर जानकारी मिली के उनके घर का ताला टूटा हुआ है। जानकारी के बाद जूनागढ़ से अहमदाबाद स्थित अपने निवास पर पहुंची चेतना चौधरी घर का ताला टूटा देख चौंक पड़ी। बंगले के पहले मंझिल पर रखी लोहे की अलमारी से 6। तोला सोने के आभूषण और तीन हजार रुपए चोरी हो गए थे। चेतना चौधरी ने फौरन पुलिस कंट्रोल रूम चोरी की जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक के घर चोरी की खबर मिलते ही नारोल पुलिस थाने के पीआई समेत वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस जांच में पता चला कि चेतना चौधरी के घर में चोर मुख्य दरवाजे के ताला तोड़कर घुसे थे और पूरे घर का सामान अस्तव्यस्त करने के पहले मंझिल पर रखी लोहे की अलमारी से रु. 20 लाख कीमत के सोने के आभूषणों पर हाथ साफ कर फरार हो गए।

जन्म से दिव्यांग रक्षा चौधरी खुद के पैरों पर हुई खड़ी

सूरत। डिसेबल वेलफेर ट्रस्ट ऑफ इंडिया के प्रमुख और पद्मश्री अवार्ड से स मानित कनुभाई टेल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि संस्था संचालित दिव्यांग बच्चों की स्कूल में कक्षा 9 से अध्ययन करनेवाली और हाल प्रभु बी.सी.ए कॉलेज में प्रथम वर्ष में अध्ययन करनेवाली तथा संस्था संचालित हॉस्टेल में ही रहनेवाली रक्षा सतीष चौधरी, मूल निवासी गांव गोडबार, तहसील मांगरोल जिला सूरत दोनों पैर से जन्मता: 80 फीसदी दिव्यांग थी। जिससे पैर घीसते हुए चलती थी। संस्था में दाखल होने के बाद संस्था द्वारा हरमाह दिव्यांगों के लिए किए जानेवाले ऑपरेशन के प में उनकी जांच करने के बाद संस्था ने उसे जयुपीटर रूग्णालय थाने मु बई ऑपरेशन के लिए भेजा था। अस्पताल में डॉ. तरल नागडा और डॉ. जयदिप धामेले द्वारा अप्रेल 2018 में सफलता पूर्वक ऑपरेश किया गया। इसके बाद संस्था संचालित फिजियोथेरापी सेन्टर में उनका ऑपरेशन के बाद का उपचार डॉ. रोशनी पारेख द्वारा कर उसे खुद के पैरों पर खड़ा किया। ऑपरेशन और उपचार का कुल खर्च 3 लाख रूपए संस्था द्वारा किया गया। संस्था के प्रमुख कनुभाई टेलर ने दिव्यांगों को निशुल्क किए जानेवाले ऑपरेशन का लाभ लेकर खुद के पैरों पर चलने का सपना साकार करने की अपील की। इसके दिव्यांगों को संस्था का स पर्क करने को कहा गया हैं।

31 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण

अहमदाबाद। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज केवड़िया के सरदार सरोवर बांध- साधुबेट पहुंचकर वहां जारी सरदार पटेल की विश्व की सबसे विराट प्रतिमा के जारी कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आगामी 31 अक्टूबर 2018 सरदार साहब की जन्म जयंती पर इस प्रतिमा का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों द्वारा करवाने की दिशा में गुजरात सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सरदर साहब की विराटता को वैश्विक ऊंचाइयां प्रदान करने का स्वप्न संजोया है और यह उनके द्वारा प्रतिमा के लोकार्पण से साकार होगा। मुख्यमंत्री ने प्रतिमा निर्माण की साइट का निरीक्षण किया और वहां जारी कामकाज की प्रगति की जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा के निर्माण में 90 हजार मीट्रिक टन सीमेंट, 25 हजार मीट्रिक टन लोहा उपयोग में लिया जा रहा है। करीब 250 जितने इंजीनियर्स इस निर्माण कार्य में योगदान दे रहे हैं। स्टेच्यू ऑफ युनिटी का 80 प्रतिशत निर्माण कार्य स पन्न हो गया है। कंक्रीट के कार्य के बाद दो चरणों में तेजी से प्रतिमा निर्माण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रतिमा के निर्माण से केवड़िया स्थित सरदार सरोवर दुनिया के महत्वपूर्ण यात्राधाम के रूप में विकसित किया जाएगा।

रूपाणी ने कहा कि सरदार साहब का जीवन कवन राजनीति से अलिप्त था। वह हमारी युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को युगों तक प्रेरणा देते रहेंगे। यह प्रतिमा पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बने, इस प्रकार की विश्वस्तरीय सुविधाएं यहां उपलब्ध करवाई जाएंगी। ट्रायबल युजियम, मनोर य गार्डन और बोटिंग जैसी सुविधाएं विकसित कर इस स्थल को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। सरदार साहब द्वारा राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए दिए गए महत्वपूर्ण योगदान का विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा राष्ट्र को समर्पित कर उनका स मान और बढ़ाया जाएगा। सरदार साहब के कार्य हमेशा प्रेरणादायी बने रहेंगे।

नहर में डूबने से 11 साल के किशोर की मौत

भरुच। अंक्लेश्वर के कापोद्रा पाटिया के निकट नहर में डूबने से एक 11 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद किशोर का शव नहर से बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक भरुच जिले के अंक्लेश्वर में कापोद्रा पाटिया क्षेत्र के वैभव पार्क में तमिलनाडु मूल का परिवार रहता है। तमिल परिवार का 11 वर्षीय पुत्र राहुल कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहा था। रविवार की छुट्टी होने से राहुल अपने दोस्तों के साथ कापोद्रा पाटिया के निकट क्रिकेट खेल रहा था। उस दौरान गेंद नहर में जा गिरी। गेंद को बाहर निकालने के लिए राहुल नहर में कूद गया। लेकिन गेंद को निकालने के प्रयास में राहुल नहर के पानी में डूब गया। राहुल के नहर में डूबने से अन्य किशोरों में भगदड़ मच गई। खबर पाते ही राहुल के परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए।

महादेव मीडिया
रोहताश यादव 9924144499, 7015339195
वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)
हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाईन करवाने के लिए संपर्क करें।
304 केवल कॉम्पलेक्ष नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com